

**न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)**  
पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 117/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 बिजेन्द्र बोथरा पुत्र स्व. रतनलाल		1 महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. मदनलाल
2 धीरेन्द्र बोथरा पुत्र स्व. मदनलाल		2 संतोष पुत्र स्व. श्रीपालचंद
3 अतुल बोथरा पुत्र स्व. भरत बोथरा		3 श्रेणीक पुत्र स्व. श्रीपालचंद
सभी जातियान बोथरा		4 शशि पुत्री स्व. श्रीपालचंद
ओसवाल निवासीगण		5 सपना पुत्री स्व. श्रीपालचंद
गोगेलाव तहसील व जिला		6 शालू पुत्री स्व. श्रीपालचंद
नागौर हाल निवासी चेन्नई		जातियान बोथरा ओसवाल निवासीगण गोगेलाव तहसील व जिला
32 बेसिन वाटर वर्क्स, स्ट्रीट, साहूकार पेठ चेन्नई		नागौर हाल निवासी चेन्नई
		7 ग्राम पंचायत गोगेलाव जरिये सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत
		गोगेलाव पंचायत समिति, नागौर तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति-

- 1 कान्ता बोथरा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।
- 2 श्री शफीक खिलजी अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से।

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994**

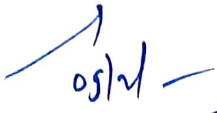
**निर्णय**

दिनांक 09.02.2026

1- यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा मिसल संख्या 05/2016-17 द्वारा पट्टा सं. 24 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.09.2019 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 14.10.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से श्री शफीक खिलजी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 7 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैरहाजिर रहे हैं। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन में मिसल संख्या 05/2016-17 की फोटोप्रति, पट्टा संख्या 24 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 05.03.2018 की फोटोप्रति, आपसी बंटवारे की लिखापट्टी की फोटोप्रति, राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के चेन्नई संस्करण की दिनांक 19.06.2024 की फोटोप्रति, दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के नागौर संस्करण की दिनांक 12.12.2024 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत गोगेलाव का रिकॉर्ड मंगाया गया।

2- उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि -

2(1)- अप्रार्थीगण ने आपसी मिलावट व अपराधिक षडयंत्र के तहत विवादित सदोष तैयार किया गया कथित पट्टा स्पष्ट रूप से फर्जी, नुमाईशी, अवैध व शून्य प्रभावी शुरू से हुआ, रहा व है जिसे निगरानी के जरिये निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है क्योंकि विवादित सम्पति अपीलान्टस की पुश्तैनी अविभाजित सम्पति रही है जिसका पक्षकारान के मध्य आज तक किसी सक्षम न्यायालय से कोई बंटवाडा आदि नहीं हुआ है सभी का संयुक्त कब्जा व संयुक्त स्वामित्व बिन्दु उतराधिकार अधिनियम व अन्य विधिक प्रावधानो अनुसार हुआ, रहा व है तथा कुटुम्ब के किसी सदस्य विशेष अकेलो को संपूर्ण सम्पति का पट्टा बनवाने का अधिकार किसी भी प्रावधान के तहत न तो था न है।

  
**अपर कलक्टर, नागौर**

2(2)– अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थीगण सं. 2 से 6 के पिता स्व. श्रीपालचंद ने आपस में षडयंत्र करके व ग्राम पंचायत गोगेलाव को अपने अपराधिक षडयंत्र में शामिल करते हुए व अनुचित दबाव, प्रभाव मिलीभगती करते हुए प्रार्थीगण सहित भैरूदानजी के दीगर वारिसान को सदोष हानि पहुँचाने व अपने आप को सदोष लाभ पहुँचाने के बेईमानीपूर्वक आशय से मिथ्या घोषणा के दस्तावेज तैयार कर छल कपट व धोखाधड़ी करते हुए तथाकथित पुश्तेनी अविभाजित सम्पति का पट्टा तैयार किया गया है क्योंकि कथित सम्पति पर भैरूदानजी के वारिसान प्रार्थीगण सहित दीगर सदस्यों का शुरू से लेकर आज दिन तक बहेसियत सहस्वामित्व संयुक्त कब्जा उपयोग उपभोग रहता चला आया है, उक्त सम्पति प्रार्थीगण की पुश्तेनी सम्पति रही है। यहाँ यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि ग्राम पंचायत में कथित पट्टा हेतु जो कार्यवाही की गयी उनमें भी उक्त सम्पति को पुश्तेनी होना बताया है इस प्रकार सम्पति पुश्तेनी होना स्वीकार सुदा तथ्य है तथा अभी तक पक्षकारों के मध्य विधिवत विभाजन नहीं होने से सभी का विधिक हक हिस्सा है ऐसी स्थिति में उक्त कथित पट्टा अकेले अप्रार्थीगण को बनाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है ऐसे अवैध पट्टे को संयुक्त सम्पति के सहस्वामियों में से कोई भी चुनौती देकर निरस्त करवाने का विधिक अधिकार रखता है इस कारण प्रार्थीगण यह निगरानी अपने विधिक अधिकारों के तहत पेश कर रहे हैं। चूंकि निगरानी केवल अप्रार्थीगण के नाम से जारी कथित फर्जी पट्टे को निरस्त करवाने के लिये है इसलिये कथित पट्टे में दर्ज पट्टाधारी व मृत पट्टाधारी के वारिसान ही आवश्यक पक्षकार हैं सम्पति के दीगर सहस्वामियों के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं होने से उनको पक्षकार बनाये जाने की कतई आवश्यकता नहीं है इन परिस्थितियों में निगरानी हाजा स्वीकार की जाकर कथित पट्टा जैर निगरानी विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2(3)– अप्रार्थी सं. 1 व स्व. श्रीपालचंद अन्यंत ही चतुर व चालाक व्यक्ति होने से उन्होंने ग्राम पंचायत गोगेलाव के सरपंच व अपने अन्य सहयोगियों से मिलावट व अपराधिक षडयंत्र कर उक्त पुश्तेनी अविभाजित सम्पति का कथित सरासर फर्जी पट्टा बाले बाले तैयार किया है। यहाँ यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि प्रार्थीगण को यह भी जानकारी हुई है कि कथित सम्पति के पट्टा बनाने से पूर्व व उसके पश्चात दीगर सहस्वामी कमलचंद बोथरा पुत्र रतनलाल जी ने भी ग्राम पंचायत, जिला कलक्टर सहित मुख्यमंत्री राज सरकार को आपति आवेदन पेश किये गये तथा ग्राम पंचायत को भी लिखित में शिकायत पेश की कि उक्त सम्पति अविभाजित है बिना सभी की सहमति के पट्टे नहीं बनावे तथा उक्त सम्पति के संबंध में बाले बाले कोई पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश करे तो पट्टा बनाने से पूर्व हम दीगर पक्षकारों व सहस्वामियों को सुना जावे, उक्त पत्र ग्राम पंचायत गोगेलाव को प्राप्त होने की पावती भी मिल गयी तथा ग्राम पंचायत गोगेलाव की जानकारी में यह तथ्य आ गया कि उक्त सम्पति अप्रार्थी महेन्द्रकुमार व स्व. श्रीपालचंद अकेलो की कब्जासुद स्वामित्व की नहीं है। इसके बावजूद खुले आम कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व दीगर सहस्वामियों कब्जाधारियों के हितों की अनदेखी करते हुए गैर कानूनी रूप से कथित पट्टा जारी किया गया है। जो स्पष्ट रूप से विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

2(4)– यहाँ यह तथ्य भी दर्ज करना महत्वपूर्ण होगा कि अपीलान्त ने हाल ही में सभी दस्तावेजों की जानकारी की व कुटुम्ब के सहस्वामियों के पास इस पुश्तेनी अविभाजित सम्पति बाबत उपलब्ध दस्तावेजात को प्राप्त करने व छानबीन करने पर यह भी पता चला कि दिनांक 28.02.18 को ग्राम पंचायत गोगेलाव को कमलचंद बोथरा पुत्र रतनलाल ने पत्र लिख कर निवेदन किया था कि कथित पट्टों को रद्द किया जावे उस पर संज्ञान लेते हुए और गलती को स्वीकार करते हुए दिनांक 05.03.18 की ग्राम पंचायत की नियमित बैठक में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ने प्रस्ताव सं. 3 रखा कि मिसल नं. 5/16-17 एवं 88/17-18 पर फैसला व जारी पट्टे गलत तथ्यों और मौका कमेटी की मिथ्या रिपोर्ट पर बने हैं इन्हें निरस्त किया जावे, जिसकी एक सत्यापित प्रति कमलचंद बोथरा पुत्र रतनलाल पौत्र भैरूदान बोथरा को भी दी गयी तथा सभी कोरम में उपस्थित पदाधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ उक्त प्रस्ताव बैठक रजिस्टर में दर्ज किया गया। इस प्रकार स्वयं ग्राम पंचायत ने कथित पट्टा को अवैध व गैर कानूनी मान लिया है तथा निरस्त किये जाने का ग्राम सेवक / पदेन सचिव का प्रस्ताव भी ग्राम पंचायत में लिया गया है इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने

09/11  
अपर कलक्टर, नागौर

आज तक कथित पट्टा को निरस्त नहीं किया है तथा उसकी आड में अप्रार्थीगण मौके की स्थिति में परिवर्तन करने व सम्पत्ति को खुर्द बुर्द, हस्तान्तरण आदि करने पर आमादा होने से प्रार्थीगण को उक्त पट्टा करवाने हेतु यह निगरानी पेश करनी आवश्यक हुई है तथा उपरोक्त हालात में उक्त पट्टा निरस्त किये जाने में किसी प्रकार की कोई कानूनी बाधा नहीं है ग्राम पंचायत भी अपने उक्त पट्टा निरस्त करने के प्रस्ताव से पाबंद है। कथित फर्जी पट्टो लेकर हुई तमाम पत्र व्यवहार की कार्यवाही, समय समय पर हुई शिकायत, सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद, ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये पट्टा निरस्त का प्रस्ताव दिनांक 5.3.18 पक्षकारान के पूर्वजो द्वारा लिखे गये पुराने पत्रो, कमलचंद द्वारा स्टांप पर तैयार की गयी स्व. भैरूदानजी की वंशावली, ग्राम पंचायत को भेजी गयी उजरदारी, पूर्वज दादा भैरूदानजी व उनके भाईयो व पुत्रो का आपसी अधिकार पत्र, मुंडिया लिपि में रतनलाल की लिखावट में मय हिन्दी अनुवाद सहित जो लिखावटी आज से करीब 85 वर्ष पुरानी है।

2(5)- यहाँ यह तथ्य भी दर्ज करना आवश्यक होगा कि तथाकथित पट्टो के लिये जो आवेदन पेश हुआ है उसमें आवेदनकर्ता श्रीपालचंद व महेन्द्रकुमार है जबकि हस्ताक्षर केवल श्रीपालचंद बोथरा के ही है तथा वह भी किसी दलाल व्यक्ति द्वारा किये हुए प्रतीत होते हैं जो संभवतया फर्जी पट्टा बनाने के षडयंत्र में भूमाफिया दलाल लोग षडयंत्र में शामिल होने की संभावना को स्पष्ट प्रकट करता है। जहाँ तक पट्टा की विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है पट्टा के संबंध में आम सूचना प्रकाशन करवाये जाने का कायदा व नियम है पत्रावली में ऐसी आम सूचना प्रकाशन संबंधी आदेशित लाईनो में कांटछांट है इन सभी परिस्थितियों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत का एक मात्र उद्देश्य गलत तौर पर पट्टे जारी करना था जिससे ऐसे फर्जी, अवैध, बिना अधिकार के व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व पुश्तेनी सम्पत्ति पर काबिज सहस्वामियों व विधिक उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना केवल दो सदस्यों के नाम पट्टा जारी किये जाने से ऐसा पट्टा शुरू से ही अवैध रहा है व इससे न तो प्रार्थीगण व दीगर सहस्वामियों के विधिक अधिकार समाप्त हो सकते हैं न ही अप्रार्थीगण को कोई विशेष विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं लेकिन चूंकि आज दिन पट्टे बने हुए अप्रार्थीगण के पास है जिनका अब वे दुरुपयोग कर उतरोतर सम्पत्ति हस्तान्तरण करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय से पट्टा निरस्त करवाया जाना आवश्यक होने से इस हेतु यह निगरानी पेश है। अप्रार्थीगण को यह भी जानकारी हो गयी है कि ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक / पदेन सचिव ने भी पट्टा गलत जारी होना मानकर प्रस्ताव ग्राम पंचायत में लिया हुआ है फिर भी भूमाफियों व दलालों के बहकावे में आकर सम्पत्ति को उतरोतर और मिथ्या घोषणा करके खुर्द बुर्द हस्तान्तरण करने की फिराक में है जिससे प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों पर खतरे के काले बादल मण्डराने लग गये हैं ऐसी स्थिति में निगरानी के क्षेत्राधिकार के जरिये उक्त पट्टे की पत्रावली तलब कर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दिनांक 5.3.18, उजरात निगरानी व संलग्न दस्तावेजात की जांच कर पट्टा निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

2(6)- इस प्रकार विवादित सम्पत्ति स्व. भैरूदान के वारिसान की पुश्तेनी संयुक्त कब्जासुद, सहस्वामित्व की संपदा रही है अप्रार्थी सं. 1 व स्व. श्रीपालचंद अकेलो को इस तरह से पट्टे बनवाने का कोई अधिकार नहीं है छल कपट व धोखाधड़ी से की गयी अपराधिक कार्यवाही है जिनके संबंध में अलग से पुलिस विभाग में तमाम षडयंत्रकारियों के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही संस्थित की जायेगी।

3-अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूरी पालना की है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपना कर पंचो की समिति गठित कर मौका निरीक्षण करवा कर विधिवत आपति नोटिस सूचना चस्पा करके व किसी प्रकार की आपति नहीं आने पर नियमानुसार पट्टा जारी किया था। निगरानीकर्ता ने विधि सम्मत पट्टे को नियम व विधि विरुद्ध होने के मिथ्या अभिवचन दर्ज किये हैं। निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

09/4  
अपर क्लर्क, नागौर

4- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत गोगेलाव की मिसल संख्या 5/2016-17 द्वारा जारी पट्टा सं 24, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.03.2018 को प्रस्ताव संख्या 03 लिया जाकर अंकन किया कि पट्टा मिसल नम्बर 88/17-18 व 05/2016-17 दोनों पट्टा फाइल श्रीपालचंद बोथरा पुत्र भैरूदान बोथरा एवं महेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल बोथरा के नाम से जारी किए गए हैं, जो मौका कमेटी द्वारा गलत निरीक्षण व पूर्वजों की अविभाजित सम्पत्ति के गलत तथ्यों के आधार पर जारी किए गए हैं, जो निरस्त किए जावे। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, जिसमें ऐसा कोई दस्तावेज नहीं पाया गया जिससे यह माना जा सके कि उक्त पट्टा सुद जायगा अप्रार्थी संख्या 01 महेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल व श्रीपालचंद बोथरा पुत्र भैरूदान की स्वअर्जित हो, या पुस्तैनी हो या पट्टा धारियों के अकेले के बंट, कब्जा, स्वामित्व या उपभोग की हो। उक्त सभी तथ्यों का अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत गोगेलाव ने उक्त पट्टा बनाते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमों की पालना किये बिना जारी किया गया है। अप्रार्थीगण ने उक्त प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.03.2018 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हो? ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा में इस पत्रावली में पेश नहीं किया। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत गोगेलाव, पंचायत समिति, नागौर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पंचायत द्वारा मिसल संख्या 5/2016-17 द्वारा जारी पट्टा सं 24 के संबंध में उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान में रखते हुए मौके की स्थिति रिकार्ड पर लेवे तथा दोनो पक्षों को सुनवाई, सबूत आदि का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

6- निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/11/18  
(चम्पालाल जीनगर)

अपर कलक्टर, नागौर  
अपर कलक्टर, नागौर